Entry of British Food Processing Companies in India.

*68. SHRI ASHOK NATH VERMA :

SHRI YASHWANT SIN HA:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the British Food Processing Companies have offered technology for the setting up of vitamin fortified -Biscuit Plants in India for the children of the poor in the villages and the (tribal areas as one biscuit would supply vitamins required for a child in a day as reported in the Hindustan Times of 6th July, 1989:

(b) if so, the names and addresses of the British Food Processing Companies which have offered such technology to the Indian Food Processing Industry ;

(c) whether the British Food Proccessing Companies which have offered vitamin fortified biscuits manufacturing technology are, on equity participation basis or their offer is part of the British Aid to India ; and

(d) what are the names and addresses of the authorities to be contacted for the transfer of such technology for Indian food Processing Companies ?

THE MINISTFR OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER) • *(a)* to (d) On his recent visit to the United Kingdon. the Minister of State for Food Processing Industries had discussions with various British Companies on possibilities of providing technical and financial collaboraion in India. While during the disussion there was some general' mention of possibility of production of Yitamin fortified Biscuits, no concrete proposal in this regard has yet been received.

आवास समितियों को भूमि के आवंटन में विलम्ब

*69. **श्री राम जेठमलानी •**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1989 के "नवभारत टाइम्स" में "छः साल से जमीन पाने का इंतजार है" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त समाचार के अनुसार सरकार ने गत वर्षों के दौरान भूमि के आवंटन हेतु सहकारी आवास समितियो को आश्वासन दिए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण सरकार ने सभी आवास समितियों को भूमि का आबंटन करने में अपनी असमर्थता दर्शायी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने विगत में किस आधार पर आश्वासन दिए थे ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमति मोहसिना किदवई) : जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार सहकारी सामूहिक आवास समितियों की भूमिका को महत्व देती रही है। अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण, की विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत पिछले बकाया पंजीकृत व्यक्तियों तथा भूमि की सीमित उपलब्धता होते हुए भी, उपनकलां परिसर में कुछ, सरकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव है । उपनकलां परिसर से संबंधित योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । अतः इस स्थिति में यह बताना मुश्किल है कि 1983 से पंजीकृत समितियों की भूमि की आवश्यकताओं को पूर्ण करना कहां तक संभव होगा ।